RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 01
अंक : 123
दि. 02.09.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.
Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री 2 सितंबर को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 सितंबर को दोपहर साढ़े 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित करेंगे। जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से धन उपलब्ध कराना है। जीविका के सभी पंजीकृत कलस्टर-स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे। इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि का योगदान करेगी।

बाढ़ से तबाही : चीन से दिल्ली लौटते ही पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम मान को लगाया फोन, जानिए क्या हुई दोनों के बीच बातचीत?

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन के तियानजिन शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। चीन से दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सीएम भगवंत मान से पंजाब में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने सीएम मान राज्य को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है।

सीएम मान ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र

पंजाब में आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। इसके चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से 60,000 करोड़ रुपये के लंबित फंड तुरंत जारी करने की मांग की थी। मान

ने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के नियमों में संशोधन की भी अपील की थी, ताकि प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जा सके।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी उठाया मुद्दा

पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम मान ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 828 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जिससे राज्य की ग्रामीण कनेक्टिविटी पर प्रभाव पड़ सकता है।

होशियारपुर के कई गांव बाढ़ में डूबे

भारी बारिश के कारण रविवार को होशियारपुर जिले के कुछ गांवों में बाढ़ आ गई, जबकि कपूरथला जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र के लोगों से ऊपरी पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

स्कूलों में छुट्टी घोषित

राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने की अवधि तीन सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने 27 से 30 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित की थीं।

सीएम योगी से मिले संजय निषाद, अपने बयानों को लेकर दी सफाई; गोरखपुर में दी थी गठबंधन तोड़ने की चेतावनी

लखनऊ, (जीएनएस)। भाजपा गठबंधन को लेकर दिए गए बयानों से उठे विवादों के बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ उनके पुत्र अमित निषाद भी थे। सूत्रों का कहना है कि संजय निषाद ने अपने बयानों को लेकर मुख्यमंत्री को सफाई दी है। हालांकि निषाद ने इसको शिष्टाचार मुलाकात बताया है।

बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में निषाद पार्टी के अधिवेशन में ही संजय निषाद ने भाजपा गठबंधन पर निशाना साधा था। इसके बाद गोरखपुर में भी भाजपा को गठबंधन तोड़ने की चेतावनी तक दी थी। इसके बाद से वे लगातार गठबंधन विरोधी बयान देकर चर्चा में थे। वहीं, सूत्रों का कहना है कि संजय निषाद ने बयानों पर सफाई देने के साथ ही विभागीय और पार्टी से संबंधित कुछ मामलों को भी सीएम के सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने उनके सभी मामलों का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स के माध्यम से कहा कि बुलेट से बैलेट के सिद्धांत को ही अपना अलग संविधान मानने वाली अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तिकड़ी है। यह तिकड़ी मिलकर राजनीति में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी जैसे तीन समाज विरोधी खतरनाक आयामों के भी प्रतीक हैं। आज इनकी स्थिति चोर-चोर मौसेरे भाई वाली है। लेकिन इनकी दाल नहीं गलने वाली है।

एयर मार्शल संजीव घुरटिया एवीएसएम वीएसएम ने एयर ऑफिसर-इन-चार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार संभाला

(जीएनएस)।

एयर मार्शल संजीव घुरटिया एवीएसएम वीएसएम ने 01 सितंबर, 2025 को वायु सेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने उन सशस्त्र बलों के जवानों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।

एयर मार्शल संजीव घुरटिया एवीएसएम वीएसएम ने वायुसेना की एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग शाखा में सितंबर 1988 में कमीशन प्राप्त किया था। वे प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, एयर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, बेंगलुरु और एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज, बेंगलुरु के पूर्व छात्र हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में वे जीईसी, जबलपुर, बिट्स पिलानी और मद्रास विश्वविद्यालय के भी पूर्व छात्र हैं और उन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वे

रॉयल एयरोनॉटिकल सोसाइटी, लंदन, एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के फेलो हैं। वे आईएसओ 45,000 (ओएच एंड एसएमएस) के लीड ऑडिटर और सोसाइटी ऑफ फ़्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स, अमरीका के एसोसिएट सदस्य हैं।

वायु सेना अधिकारी ने अपने 37 वर्षों के शानदार करियर में वायुसेना और विदेश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कई महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। एयर ऑफिसर-इन-चार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार संभालने से पहले वे मुख्यालय एमसी में वरिष्ठ मेंटेनेंस स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे।

उनकी विशिष्ट सेवा के लिए वायु सेना अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2016 में 'विशिष्ट सेवा पदक' और 2025 में 'अति विशिष्ट सेवा पदक' से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन कांगो में सेवा करते हुए उन्हें संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर द्वारा भी प्रशंसा मिली।

प्रधानमंत्री 'सेमीकॉन इंडिया - 2025' का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे नई दिल्ली के यशोभूमि में 'सेमीकॉन इंडिया - 2025' का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री 3 सितंबर को सुबह लगभग 9:30 बजे से भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। 2 से 4 सितंबर, 2025 तक चलने वाला यह तीन दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, सशक्त और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इसमें सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, सेमीकंडक्टर फैब और उन्नत पैकेजिंग परियोजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार, निवेश के अवसर

राष्ट्रपति ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुईं

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज (1 सितम्बर, 2025) कर्नाटक के मैसूरु में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग (एआईआईएसएच के हीरक जयंती समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य समस्याओं की तरह, बोलने और सुनने संबंधी समस्याओं के लक्षणों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान और उनके निदान के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। समाज को जागरूक होना चाहिए और बोलने और सुनने की समस्याओं से पीड़ित लोगों के प्रति सहयोग और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। उन्हें खुशी है कि एआईआईएसएच इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक अखिल भारतीय संस्थान के रूप में, एआईआईएसएच को भारत और

विदेशों के संस्थानों के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित होने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआईआईएसएच द्वारा स्थापित 'समावेशी थेरेपी पार्क' भारत और विदेशों में एक आदर्श के रूप में कार्य कर रहा है, जिसे संचार विकारों से प्रभावित बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। 'एआईआईएसएच आरोग्य वाणी' भी संचार विकारों और उनकी शीघ्र पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक अनूठी पहल है।

उन्होंने कहा कि देश का एक अग्रणी संस्थान होने के नाते, एआईआईएसएच संचार विकारों से संबंधित राष्ट्रीय नीति-निर्माण में भी सलाह दे सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज, तकनीक हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नवीनतम तकनीकों का उपयोग वाणी और श्रवण संबंधी अक्षमताओं को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगा। लेकिन नवीनतम तकनीकों और उपकरणों को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए, देश में उनका विकास और निर्माण आवश्यक है।

उदाहरण के लिए, कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे उपकरणों को कम लागत पर उपलब्ध कराने के लिए, हमें उनके निर्माण में आत्मनिर्भर बनना होगा। एआईआईएसएच जैसे संस्थानों को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर, एआईआईएसएच राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान को और मजबूत कर सकता है। यह संस्थान देश के जाने-माने अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि एआईआईएसएच जैसे संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवाचार की भावना और संवेदना के साथ काम करें और ऐसी तकनीकें विकसित करें जो वाणी और श्रवण बाधित लोगों को न केवल सामान्य जीवन जीने में सक्षम बनाएँ, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकें।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार विभिन्न कल्याणकारी पहलों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए एक बाधा-मुक्त वातावरण तैयार कर रही है ताकि वे बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन में प्रगति कर सकें।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ने बुलाई राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों की बैठक

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आज राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ एक बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता, डीएफपीडी, भारत सरकार के सचिव, श्री संजीव चोपड़ा ने की। इस बैठक का उद्देश्य आगामी खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2025-26 में फसलों की खरीद व्यवस्था पर चर्चा करना था। बैठक के दौरान, आगामी केएमएस 2025-26 के लिए धान खरीद (खरीफ फसल) का अनुमान 463.50 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल के रूप में और मोटे अनाज/बाजरा (श्री अन्न) की खरीद का अनुमान 19.19 एलएमटी तय किया गया है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस को संबोधित किया

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी से सुधारोन्मुख, तकनीक-संचालित परिवर्तनकारी संस्थान के रूप में उभरने का आग्रह किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के 65वें स्थापना दिवस को संबोधित किया और दीक्षा 2.0 सहित कई पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने ओडिशा की 100 महान हस्तियों के जीवन और योगदान पर आधारित पुस्तक 'उत्कल जननींकर सुजोग्य संतान' का भी विमोचन किया।

एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस समारोह में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री संजय कुमार; भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री चामू कृष्ण शास्त्री; एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी; यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार; इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ; और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रो. जेएस राजपूत के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी की नई शैक्षिक पहलों का उद्घाटन करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री प्रधान ने एनसीईआरटी को भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक प्रतिष्ठित संस्थान बताया। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी देश के शैक्षिक परिदृश्य का स्तंभ रहा है, जिसने अद्वितीय प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ छात्रों के भविष्य को आकार दिया है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी को 'ज्ञान-कुंभ' बताते हुए अपनी स्थापना के बाद से शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने एनसीईआरटी से सुधारोन्मुख, तकनीक-संचालित और वैश्विक सर्वोत्तम विधियां अपनाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सतह वाली बारहमासी पक्की सड़कों की सुविधा प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय

- राज्य के सभी जिलों में पंचायत के अंतर्गत आने वाली नियोजित सड़कों के रिसर्फेसिंग और आनुषंगिक कार्यों के लिए 2609 करोड़ रुपए मंजूर
- 4196 किलोमीटर लंबाई की 1258 सड़कों की रिसर्फेसिंग सहित अन्य कार्य किए जाएंगे

गांधीनगर, 01 सितंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से बेहतर सतह वाली और बारहमासी पक्की सड़कों की सुविधा उपलब्ध कराने का जनहितैषी दृष्टिकोण अपनाया है।

मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों के पंचायत के अंतर्गत आने वाली आवश्यक नियोजित सड़कों की रिसर्फेसिंग और आनुषंगिक कार्यों के लिए 2609 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

इस बड़ी धनराशि से जिन सड़कों के रिसर्फेसिंग सहित अन्य कार्य किए जाएंगे, उनमें उत्तर गुजरात क्षेत्र में 1609 किलोमीटर लंबाई की 487 सड़कें, दक्षिण गुजरात क्षेत्र में 1528 किलोमीटर लंबाई की 499 सड़कें और सौराष्ट्र क्षेत्र में 1059 किलोमीटर की 272 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।

जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण नागरिकों एवं अग्रणियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष बारहमासी सड़कों की सुविधा की मांग की थी। इस पर त्वरित और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4196 किलोमीटर लंबाई की 1258 सड़कों की मरम्मत और रिसर्फेसिंग कार्यों के लिए यह धनराशि आवंटित की है।

इन सड़कों के रिसर्फेसिंग एवं अन्य आनुषंगिक कार्यों के पूरा होने पर ग्रामीण क्षेत्रों का सड़क नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। साथ ही, छोटे गांवों में भी आंतरिक एवं शहरों के साथ परिवहन आसान हो जाएगा।

श्रीमती टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक (सीजीए) का पदभार ग्रहण किया

भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) की 1991 बैच की अधिकारी श्रीमती टीसीए कल्याणी ने आज वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक (सीजीए) का पदभार संभाला। वह इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाली 29वीं अधिकारी हैं।

श्रीमती कल्याणी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्वर्ण पदक के साथ राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्नातकोत्तर और पश्चिमी यूरोपीय अध्ययन में एम.फिल. की उपाधि भी प्राप्त की है।

सम्पादकीय

विश्व की बदलती इस व्यवस्था में उभरता भारत

ट्रंप टैरिफ से भारतीयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्कि इस बात के लिए गर्व करने की जरूरत है कि पैर खींचने वाला कोई एक है तो हाथ पकड़कर आगे बढ़ने वालों की कतार लगी पड़ी है। विश्व की बदलती इस व्यवस्था की जब भी समीक्षा होगी तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख अवश्य होगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोपेसर रिचर्ड डेविड वूल्फ ने चूहे और हाथी की तुलना करके कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 50 प्रतिशत टैरिफ उस चूहे की तरह है जो भारत की हाथी जैसी अर्थव्यवस्था को मुक्का मार रही है तो इसे उतना महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। प्रोपेसर रिचर्ड डेविड वूल्फ एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जो आर्थिक पद्धति और वर्ग विश्लेषण पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह मेसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में प्रोपेसर एमिरेट्स हैं। प्रोपेसर वूल्फ ने इस आधार पर यह उपमा दी थी कि अमेरिका विश्व आर्थिकी में अमेरिका की अगुवाई वाले ब्लाक जी-7 का योगदान 28 प्रतिशत रह गया है जबकि ब्रिक्स जिसमें भारत और चीन हैं उसका योगदान 35 प्रतिशत हो गया है। यही 7 प्रतिशत का अन्तर अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व भारत करेगा और यदि ट्रंप का भारत, चीन, रूस और अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ इसी तरह का असय व्यवहार रहा तो डालर में व्यापार का विकल्प खोज कर अमेरिकी बादशाहत को ठेंगा दिखा देगा ब्रिक्स। अर्थशास्त्र में अमेरिकी राष्ट्रपति कितने फिसड्डी हैं, इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह जिस भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बता चुके थे उसने 7.8 प्रतिशत की प्रत्याशित उछाल से साबित कर दिया कि भारत की तुलना पाकिस्तान से करके न सिर्प अमेरिका ने गलती की है बल्कि अब उन्हें पाताप का अवसर भी मिलने वाला नहीं है। 2025 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चीन में ऐसे वक्त में हो रही है जहां अमेरिका विरोधी आर्थिक नीतियों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने पर जो विचार हो रहा है वह अमेरिका को ही वेंद्र में रखकर हो रहा है । अपने खिलाफ सव्रिय विश्व शक्तियों के साथ भारत को धकेल कर ट्रंप ने जो गलती की उसका लाभ उठाने में यदि भारत ने देर नहीं की तो यह भारतीय नेतृत्व की सूझबूझ का ही परिणाम है। भारत चाहे तो ट्रंप के टैरिफ का जवाब दे सकता है किन्तु वह मात्र इसलिए वुछ नहीं कर रहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी है और जो लोग आज भारत के समर्थन में हैं, वे भी चाहते हैं कि भारत समय की प्रतीक्षा करे। भारत की अगुवाई में 2026 का ब्रिक्स अमेरिका के लिए इतना घातक होगा कि ट्रंप को अमेरिकी अर्थशास्त्री उनकी ऐतिहासिक भूल के लिए सदैव स्मरण करेंगे। रूस और चीन तो ब्रिक्स मुद्रा निर्धारण के लिए पहले से ही उधेड़ बुन में लगे हुए थे किन्तु भारत, ब्राजील और दक्षिण अप्रीका के नेताओं ने ऐसा न करने के लिए सुझाव दिया था। अब डालर विमुद्रीकरण में कोई बाधा नहीं है क्योंकि भारत खुद ही इसकी अगुवाई करने वाला देश बन चुका है। अमेरिका भारत का शत्रु नहीं है किन्तु ट्रंप जैसा व्यवहार कर रहे हैं वह शत्रु जैसा ही है। इसलिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था के हितों के लिए फिलहाल अमेरिकी मोहपाश से निकल कर रणनीति बनाए। अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन की एकजुटता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी किन्तु भारत ने यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ कर मुक्त समझौता (एफटीए) करके वह बाधा भी दूर कर दी जिसका डर ट्रंप दिखा सकते थे। सच तो यह है कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ने जो वुछ भी वूटनीतिक फरेबी जाल बुना है वह चीन के खिलाफ है! अमेरिकी राजनीति में जब डेमोव्रेट जीतते हैं तो वे रूस के विरोध में हो जाते हैं और चीन समर्थन करते हैं किन्तु जब रिपब्लिकन सत्ता में आते हैं तो वे रूस को अपना सहयोगी मानते हैं और चीन पर निशाना साधते हैं। एक सच्चाई ये भी है कि भारत और चीन के बीच संबंधों में कड़वाहट का कारण पाकिस्तान है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान के सामने ही आतंकवाद के संरक्षकों की फजीहत की और पहलगाम के सूत्रधारों की फजीहत कर दी।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए की उच्चस्तरीय बैठक

किसानों की शिकायतों, सुझाव व अन्य मदद के लिए एक समर्पित पोर्टल रहेगा - श्री शिवराज सिंह

किसानों को त्वरित राहत के लिए शिकायतों की नियमित समीक्षा करेंगे श्री शिवराज सिंह

किसानों के हित में सभी अधिकारी पूरी पारदर्शिता, विश्वसनीयता व संवेदनशीलता से करें काम- श्री शिवराज सिंह

नकली या घटिया खाद-बीज, कीटनाशक संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता से हो समाधान- श्री शिवराज सिंह

किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सिर्फ प्रमाणित बायोस्टियुमिलेंट ही बिकें - श्री शिवराज

(जीएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक कर, किसानों से कॉल सेंटर एवं अन्य पोर्टल्स के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के समाधान के संबंध में समीक्षा की। बैठक में श्री शिवराज सिंह ने अलग-अलग पोर्टल की जगह किसानों की सुविधा के लिए उनकी शिकायतों, सुझाव तथा अन्य सहायता के लिए एक ही समर्पित पोर्टल बनाने और समस्याओं का जल्द से जल्द समुचित निराकरण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं नियमित रूप से किसानों से मिली शिकायतों की समीक्षा करेंगे, ताकि उन्हें त्वरित राहत प्रदान की जा सकें।

किसानों से प्राप्त शिकायतों व हेल्पलाइन नंबर पर आ रही कॉल्स को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के हित में सभी अधिकारी पूरी पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं संवेदनशीलता से काम करते हुए व्यवस्था को और सुदृढ करें। व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, जिससे कि किसानों की शिकायतों का रीयल टाइम में उचित समाधान हो सकें। हम सभी की कोशिश यहीं होनी चाहिए कि किसान हर हाल में खुशहाल रहें और खेती समृद्ध हो।

बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों से, किसानों से मिलने वाली शिकायतों की जानकारी ली, जिसमें अनेक शिकायतें नकली या घटिया खाद-बीज एवं कीटनाशक के संबंध में हैं। श्री शिवराज सिंह ने इन शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से करने का निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें राज्यों में प्रवास के दौरान भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, किसानों को हमें लुटने से बचाना चाहिए और इसके लिए अमानक खाद-बीज, कीटनाशक की बिक्री पर सख्ती से रोक लगानी होगी। केंद्र के अधिकारी अपने स्तर पर कार्रवाई के साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि हमारे किसान भाई-बहनों को राहत मिल सकें। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की इन समस्याओं को हल करने में राज्यों की सहभागिता आवश्यक हो। वे स्वयं इस संबंध में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख चुके हैं, आगे वर्चुअल माध्यम से भी राज्यों से चर्चा करेंगे, ताकि किसानों को पूरी तरह से राहत मिल सकें।

अवैध बायोस्टियुमिलेंट (जैव उत्तेजक) की पूर्व में हुई बिक्री को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बायोस्टियुमिलेंट की बिक्री केवल नोटिफाइड प्रोडक्ट्स की ही हो, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया और अब तक नोटिफाइड 146 बायोस्टियुमिलेंट के अलावा अन्य बिना अनुमति प्राप्त बायोस्टियुमिलेंट की बिक्री नहीं हो, सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अधिसूचित बायोस्टियुमिलेंट के बारे में किसानों को जागरूक करने व प्रमाणित बायोस्टियुमिलेंट की सूची सोशल मीडिया द्वारा किसानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम आदि के संबंध में मिली शिकायतों की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनके संबंध में किसानों की हर शिकायत का निराकरण कर किसानों से संपर्क करके अधिकारी उनका फीडबैक भी लें। हर हाल में हमारे किसान पूर्णतः संतुष्ट होने चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी भी मौजूद थे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री चौहान को अपने सुझाव दिए।

केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सीईपीए को मजबूत करने के लिए यूएई के विदेश व्यापार मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की

भारत और यूएई ने सीईपीए की प्रगति की समीक्षा की; 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर-तेल व्यापार का लक्ष्य रखा

भारत गल्फ फूड 2026 में 1200 वर्ग मीटर के मंडप में फूड, मरीन, चाय, कॉफी और मसालों को प्रदर्शित करेगा

(जीएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को और मजबूत करने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2025 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश व्यापार मंत्री महामहिम डॉ. थानी बिन अहमद अल जायौदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया। श्री गोयल ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता और अंतर्निहित शक्तियों पर प्रकाश डाला, जिसने इसे चुनौतीपूर्ण समय में भी आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है। दोनों मंत्रियों ने पारस्परिक लाभ के लिए विविध साझेदारों के साथ काम करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की।

इस बैठक में सीईपीए के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की गई और 2030 तक गैर-तेल, गैर-कीमती धातुओं के व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के द्विपक्षीय व्यापार के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की गई। नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला रिज़िल्यन्स और स्वास्थ्य सेवा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने सीईपीए के अंतर्गत बेहतर निगरानी के लिए समय पर व्यापार डेटा के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर जोर दिया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सेवाओं पर उप-समिति की बैठक दो महीने के भीतर की जाएगी। भारतीय पक्ष ने अमीरात औषधि प्रतिष्ठान के गठन और भारतीय दवा कंपनियों की समस्याओं को दूर करने में इसकी भूमिका का स्वागत किया। बाजार पहुंच और विनियामक मुद्दों पर, दोनों मंत्रियों ने सीईपीए संयुक्त समिति में शीघ्र समाधान के लिए मामलों को उठाने पर सहमति व्यक्त की।

श्री गोयल ने भारत के बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात के बढ़ते निवेश का स्वागत किया और बहुपक्षीय व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने में डॉ. थानी के नेतृत्व की सराहना की। मंत्रियों ने व्यापार सुगमता के सहायक के रूप में यूएई में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (आईएनआर-एईडी) और भारत मार्ट जैसी पहलों के महत्व का उल्लेख किया। बैठक में भारत-यूएई साझेदारी को 21वीं सदी के एक निर्णायक एलायंस के रूप में रेखांकित किया गया, जो नवाचार, स्थिरता और साझी समृद्धि पर आधारित है।

30 अगस्त 2025 को, श्री पीयूष गोयल और डॉ. थानी बिन अहमद अल जायौदी ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ हितधारक बैठकों की सह-अध्यक्षता की। फार्मा क्षेत्र में, उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स एवं स्वास्थ्य सेवा उत्पादों के व्यापार को और सुगम बनाने के तरीकों पर विचार साझा किए। यूएई पक्ष ने पंजीकरण प्रक्रियाओं और विनियामक सुविधा में तेजी लाने पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया, जबकि भारतीय पक्ष ने यूएई अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और लेखा परीक्षा के प्रति स्वीकार्यता और तत्परता पर प्रकाश डाला। भारत-यूएई साझेदारी के तहत आयुर्वेदिक उत्पादों पर विशेष जोर देते हुए, पारंपरिक चिकित्सा में उभरते अवसरों पर भी चर्चा हुई।

खाद्य क्षेत्र में, एपीडा ने खाद्य और कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारती योजना शुरू की है, जिसके तहत 100 से ज्यादा कंपनियों को ब्रांड बनाने, उनका विस्तार करने और बिजनेस-टू-बिजनेस गठजोड़ बनाने में मदद मिलेगी। एपीडा ने दुबई में आयोजित होने वाले गल्फ फूड के 2026 संस्करण में भारत को भागीदार देश बनाने के लिए डीडब्ल्यूटीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। फूड, मरीन, चाय, कॉफी और मसालों के क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को 1200 वर्ग मीटर से ज्यादा प्रदर्शनी स्थल आवंटित किया जाएगा। यूएई पक्ष ने भारतीय खाद्य एवं पेय उद्योग की समस्याओं का समाधान किया, जिसमें उच्च खुदरा मूल्य, मूल्य मानदंड और चावल की खेपों के लिए आवश्यक परीक्षण से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

उसी दिन बाद में, श्री पीयूष गोयल और डॉ. थानी बिन अहमद अल जायौदी ने उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ एक व्यावसायिक बातचीत में भाग लिया। दोनों पक्षों ने सीईपीए पर हस्ताक्षर के बाद से तीन वर्षों में हासिल की गई ऐतिहासिक प्रगति की सराहना की, बढ़ते निवेश प्रवाह के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और भविष्य के लिए एक साहसिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की। श्री गोयल ने इस तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत की मजबूत आर्थिक वृद्धि का उल्लेख किया तथा 2027 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 32-35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के देश के लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कराधान, व्यापार नीति, व्यापार करने में आसानी और विनियामक सरलीकरण में निरंतर सुधार समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देंगे।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव ने दक्षिणी राज्यों में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई

(जीएनएस)। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया ने कर्नाटक, केरल और तेलंगाना राज्यों में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और परियोजना के समर्थकों ने भाग लिया। इस समीक्षा बैठक में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा सुगम अंतर-मंत्रालयी और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाकर समस्याओं के समाधान में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कर्नाटक में 3,658 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित 5 मुद्दों की समीक्षा की गई। केरल में 5,002 करोड़ रुपये की लागत वाली 2 परियोजनाओं से संबंधित 2 मुद्दों की पड़ताल की गई, जबकि तेलंगाना में 1,934 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 3 परियोजनाओं से संबंधित 6 मुद्दों पर चर्चा की गई।

समीक्षा की गई प्रमुख परियोजनाओं में केरल और तमिलनाडु से संबंधित त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना शामिल थी। 3,785 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा सिंगल-लाइन ट्रैक का दोहरीकरण करना है ताकि यात्रा का समय कम हो, ट्रेनों की आवृत्ति बढ़े और पूरे क्षेत्र में यात्री और माल ढुलाई में सुधार हो। परियोजना के पूरा होने पर, क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार, सड़क यातायात की भीड़भाड़ कम होने और पर्यटन एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और स्थानीय रुकावट से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया और संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और सामाजिक-आर्थिक लाभों को अधिकतम करने के लिए उनके शीघ्र समाधान की सलाह दी गई।

रिलायंस जियो की 5जी/4जी नेटवर्क के विस्तार की पहल की भी समीक्षा की गई। तेलंगाना सरकार के साथ हुई चर्चा में वन एवं वन्यजीव मंजूरी से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य देश भर के अछूते और दूरदराज के क्षेत्रों में 5जी मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करना है, साथ ही मौजूदा 4जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। एक बार कार्यान्वित होने पर इस पहल से रणनीतिक रूप से संवेदनशील और भौगोलिक रूप से दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इससे सरकार के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन को बढ़ावा मिलेगा।

डीपीआईआईटी सचिव ने परियोजना निगरानी के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों के समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की विशेष प्रणाली का लाभ उठाने वाले निजी समर्थकों के महत्व से भी अवगत कराया।

डाक विभाग ने डिजिपिन पहल को विस्तार देने के लिए ईएसआरआई इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)। डाक विभाग (डीओपी) ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सॉफ्टवेयर और समाधान प्रदाता ईएसआरआई इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ईएसआरआई इंडिया) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

डाक विभाग इस समझौता ज्ञापन के तहत, अपने डिजिपिन पोर्टल के लिए ईएसआरआई इंडिया के हाई-रिजॉल्यूशन इमेजरी और स्ट्रीट बेसमैप्स का इस्तेमाल करने में सक्षम होगा। इस सहयोग से डिजिपिन को ईएसआरआई इंडिया के लिविंग एटलस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकेगा, जिससे यह बड़े जीआईएस समुदाय के लिए सुलभ हो जाएगा। इसके अलावा, ईएसआरआई इंडिया डिजिपिन के लिए उनकी सेवाओं के निर्बाध एकीकरण हेतु डाक विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

इस समझौते का उद्देश्य डिजिपिन के विकास और कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए ईएसआरआई इंडिया के मानचित्रण समाधानों का लाभ उठाना है, जिससे डिजिपिन प्रणाली अधिक बेहतरीन व नागरिक-अनुकूल बन सके।

नई दिल्ली के डाक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में डाक विभाग और ईएसआरआई, इंडिया के नामित प्रतिनिधियों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

डाक विभाग और ईएसआरआई इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस अवसर पर डाक विभाग के सदस्य (संचालन) श्री हरप्रीत सिंह ने कहा:

ईएसआरआई इंडिया के साथ यह सहयोग डिजिपिन पहल के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ईएसआरआई के शानदार आधार मानचित्रों और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ, डिजिपिन नागरिकों तथा सरकारी सेवाओं को सटीकता व पहुंच के साथ सशक्त बनाएगा।

ईएसआरआई इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री अगेंद्र कुमार ने कहा, "हमें इस ऐतिहासिक पहल पर डाक विभाग के साथ सहयोग करने पर गर्व है। ईएसआरआई इंडिया की जीआईएस विशेषज्ञता व उन्नत मानचित्रण समाधान, डिजिपिन को एक सशक्त डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बनने में मदद करेंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता बढ़ेगी और भारत के व्यापक डिजिटल परिवर्तन में सहायता मिलेगी।"

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नियामकों के लिए वैश्विक संगोष्ठी 2025 में कहा-₹हम केवल नेटवर्क नहीं बनाएंगे, हम राष्ट्र भी बनाएंगे₹

"विनियमन कोई बंधन नहीं है, यह एक ऐसा बगीचा है जिसे पोषित किया जाना चाहिए": भारत ने जीएसआर 2025 में डिजिटल शासन में वैश्विक बदलाव का आह्वान किया

भारत के डिजिटल विनियमन मॉडल ने आईटीयू के जीएसआर 2025 में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया

श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नियामकों से केवल प्रवर्तनकर्ता नहीं, बल्कि इकोसिस्टम निमार्ता बनने का आग्रह किया

(जीएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नियामकों के लिए वैश्विक संगोष्ठी (जीएसआर) 2025 को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। श्री सिंधिया ने अपने संबोधन में, वैश्विक नियामक समुदाय से द्वारपालों से आगे बढ़कर समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम के निमार्ता बनने का एक साहसिक आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री महोदय ने "नियामकों को डिजिटल इकोसिस्टम निमार्ता बनने के लिए क्या करना होगा?" विषय पर आयोजित उच्च-स्तरीय कार्यकारी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हुए भारत को दूरदर्शिता, विश्वास और समावेशी नवाचार पर आधारित नियामक परिवर्तन के एक वैश्विक मॉडल के रूप में स्थापित किया।

नियामकों के लिए वैश्विक संगोष्ठी (जीएसआर) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है, जहाँ 190 से अधिक देशों के राष्ट्रीय आईसीटी नियामक प्राधिकरणों के प्रमुख, नीति निमार्ता, उद्योग जगत के नेता और डिजिटल विशेषज्ञ दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नियामक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं।

इस वर्ष, जीएसआर-25 का 25वाँ संस्करण, सऊदी अरब द्वारा आईटीयू के सहयोग से, 31 अगस्त से 3 सितंबर तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय "स्थायी डिजिटल विकास के लिए विनियमन" है।

श्री सिंधिया ने प्रतिष्ठित वैश्विक श्रोताओं को संबोधित करते हुए जीएसआर की तुलना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक प्रकाश स्तंभ से की और इसे एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया "जहाँ ज्ञान नवाचार को अपनाता है और जहाँ हम मिलकर अपने साझा डिजिटल भाग्य का मार्ग निर्धारित करते हैं।" केंद्रीय मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "इस वर्ष का विषय—सतत डिजिटल विकास के लिए विनियमन—तात्कालिकता और आशा से ओतप्रोत है।"

केंद्रीय मंत्री महोदय श्री सिंधिया ने सत्र के मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए ने तीन प्रमुख आयामों को रेखांकित किया जो एक डिजिटल इकोसिस्टम निमार्ता के रूप में नियामक की नई भूमिका को परिभाषित करते हैं। पहला, नियामकों को प्रतिक्रियात्मक नियम-निर्धारण से सक्रिय इकोसिस्टम डिजाइन की ओर बढ़ना होगा। इसमें सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना और अंतर-संचालनीय प्लेटफॉर्म के लिए सक्षम ढाँचे शामिल हैं। दूसरा, उन्हें नियामक सैंडबॉक्स बनाकर नवाचार को प्रेरित करना होगा, जो उपयोगकर्ता सुरक्षा या बाजार स्थिरता से समझौता किए बिना नए विचारों का परीक्षण करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। तीसरा, नियामकों को नागरिक-केंद्रित नीतियों, शिकायत निवारण व्यवस्थाओं और मजबूत डेटा सुरक्षा मानकों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र में विश्वास को समाहित करना होगा।

भारत के अनुभव को इस बदलाव के एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय मंत्री महोदय ने भारत में 5-जी सेवा शुरू होने के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला। इसमें 776 जिलों में 99.9 प्रतिशत ज़िला कवरेज हासिल करना, 30 करोड़ से ज्यादा उपयोगकताओं को जोड़ना और दुनिया में प्रति व्यक्ति डेटा उपयोग के मामले में सबसे ज्यादा उपलब्धि हासिल करना शामिल है।

इस प्रगति में नीतिगत सुधारों की प्रमुख भूमिका रही है। दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024 ने औपनिवेशिक काल की विरासतों की जगह एआई और क्वांटम युग के लिए उपयुक्त कानूनी ढाँचे को स्थापित किया है। भारत का नया डिजिटल सार्वभौमिक सेवा कोष, डिजिटल भारत निधि, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के एक ऐसे मॉडल का उदाहरण है जो देश के प्रत्येक भाग तक कनेक्टिविटी और डिजिटल समानता सुनिश्चित करता है।

उन्होंने प्रमुख भारतीय पहलों, आधार, जन धन योजना, पीएम-वाणी, भारतनेट और इंडिया पोस्ट का ज़िक्र करते हुए बताया कि कैसे नियमन डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को विकसित और विस्तारित कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ. कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि "सशक्तिकरण की जीवंत धमनियाँ" हैं, जो नागरिकों को सम्मान और अवसर से जोड़ती हैं।

केंद्रीय मंत्री महोदय श्री सिंधिया ने स्पेक्ट्रम बैंडों में सामंजस्य स्थापित करने, लागतों को युक्तिसंगत बनाने और आपदा-प्रतिरोधी हरित नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करने हेतु एक वैश्विक मानक के रूप में एक डिजिटल उपभोक्ता चार्टर के विकास का प्रस्ताव रखा।

भारत का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक संतुलित नियामक दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए, जो सुरक्षा, नैतिकता और समावेशिता सुनिश्चित करते हुए नवाचार का समर्थन करे। इसका लक्ष्य एक ऐसा नियामक ढांचा स्थापित करना है जो खुला, आसान और जनहित के लिए बना हो। माननीय मंत्री ने जोर दिया कि भारत नवाचार में बाधा डालने वाले प्रतिबंधात्मक नियम लागू नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही, वह एआई के दुरुपयोग के संभावित खतरों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी उद्देश्य से, भारत ने 2024 में 10,371.92 करोड़ रुपये (1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बजट के साथ इंडियाएआई मिशन शुरू किया।

केंद्रीय मंत्री महोदय श्री सिंधिया ने विकसित होते नियामक परिदृश्य पर विचार करते हुए कहा कि विनियमन अब लाइसेंस जारी करने या दंड लागू करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दृष्टिकोण निर्धारित करने, विश्वास बनाने और भविष्य के लिए तैयार समाजों को आकार देने के बारे में है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

उत्तर रेलवे के कठुआ-माधोपुर पंजाब सेक्शन में ब्रिज नं 17 पर मिसअलाइमेंट के चलते रेल यातायात प्रभावित

उत्तर रेलवे के कठुआ-माधोपुर पंजाब सेक्शन में डाउन लाइन पर ब्रिज संख्या 17 पर मिसअलाइमेंट होने के कारण रेल यातायात स्थगित किया गया है। जिसके कारण अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

आंशिक निरस्त ट्रेनें:-

- 02 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस फिरोजपुर केंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी, इस प्रकार यह ट्रेन फिरोजपुर केंट और जम्मू तवी के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 03 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक ट्रेन संख्या 19224 जम्मू तवी-साबरमती एक्सप्रेस फिरोजपुर केंट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी, इस प्रकार यह ट्रेन जम्मू तवी और फिरोजपुर केंट के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

निरस्त ट्रेनें:-

1. 7,14,21 और 28 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19415 साबरमती-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
2. 2,9,16,23 और 30 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19416 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-साबरमती एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
3. 06 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 12473 गांधीधाम-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
4. 04 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 12474 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-गांधीधाम एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
5. 02 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 12475 हापा-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
6. 03 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 12477 जामनगर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
7. 06,13,20 और 27 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मू तवी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
8. 8,15,22 और 29 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19028 जम्मू तवी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
9. 7,14,21 और 28 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19107 भावनगर टर्मिनस-एमसीटीएम ऊधमपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
10. 8,15,22 और 29 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19108 एमसीटीएम ऊधमपुर-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

शिव अनंता फ्लैट्स, चांदखेड़ा में गणेश उत्सव-2025 का सफल समापन

अहमदाबाद- शिव अनंता फ्लैट्स में हाल ही में गणेश उत्सव का उत्साह और सामुदायिक भावना के साथ सफल समापन हुआ। 27 अगस्त, 2025 को गणेश स्थापना पूजा के साथ शुरू हुए इस उत्सव ने निवासियों को कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एक साथ लाया।

पूरे उत्सव के दौरान, निवासियों ने हर दिन सुबह और शाम की गणपति आरती में भाग लिया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। नासिक ढोल की लयबद्ध धुन ने भगवान गणेश के आगमन और विदाई दोनों को चिह्नित किया, जिससे एक जीवंत और उत्सव का माहौल बन गया। 28 अगस्त को गणेश भजन कार्यक्रम का आयोजन एक विशेष आकर्षण था, जहाँ निवासियों ने भक्ति गीत गाए

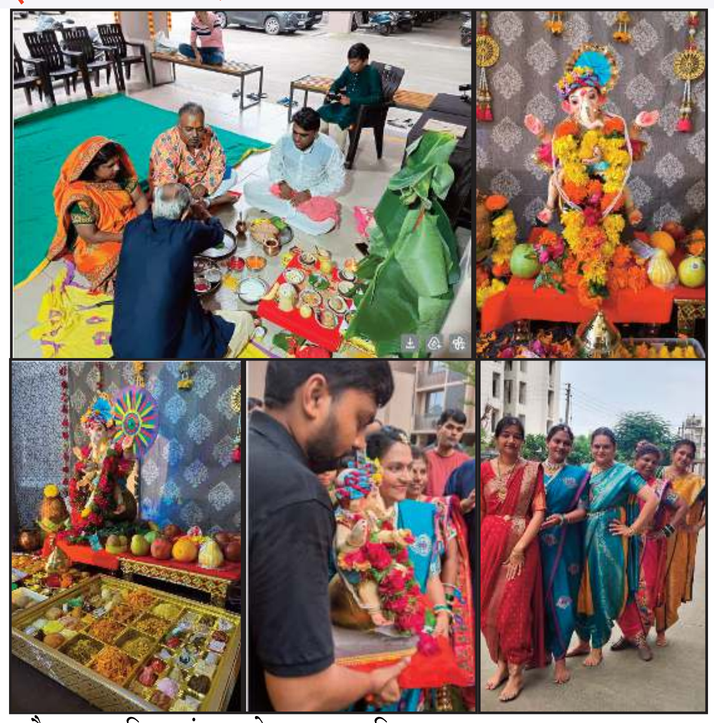

और सामुदायिक बंधन को मजबूत किया।

इस उत्सव में 30 अगस्त को आयोजित सत्यनारायण कथा भी शामिल थी, जिसने सभी उपस्थित लोगों के लिए एक शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। उत्सव का समापन 31 अगस्त को गणेश विसर्जन के साथ हुआ। विदाई समारोह में सुबह और शाम की आरती के बाद, नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल थे। प्रतिमा का विसर्जन बगीचे में बनाए गए एक विशेष जल कुंड में सम्मानपूर्वक किया गया, जिससे पर्यावरण-अनुकूल उत्सव सुनिश्चित हुआ।

इस वर्ष गणेश उत्सव की सफलता में निवासियों की भारी भागीदारी ने समुदाय में एकता और साझा खुशी की भावना को बढ़ावा दिया।

पश्चिम रेलवे के 6 कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता प्रमुख विभागाध्यक्षों तथा महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार प्राप्तकताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं।

मुंबई,

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में 6 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया, जिनके योगदान से सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित हो सका। ये कर्मचारी जून एवं जुलाई, 2025 माह के दौरान ड्यूटी में सतर्कता बरतते हुए किसी भी अप्रिय घटना को टालने में सफल रहे। इन 6 कर्मचारियों में अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडल से दो-दो कर्मचारी, जबकि मुंबई सेंट्रल एवं भावनगर मंडल से एक-एक कर्मचारी शामिल हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति समर्पित रहकर दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं। इन कर्मचारियों ने संरक्षा के विविध क्षेत्रों जैसे कि ब्रेक बाइंडिंग या हॉट व्हील एक्सल, आपातकालीन ब्रेक लगाकर अप्रिय घटना को रोकने, मानव जीवन की रक्षा करना आदि में सक्रिय योगदान देकर ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने में अपना अदम्य उत्साह और प्रतिबद्धता दिखाई।

पश्चिम रेलवे को इन सभी कर्मचारियों पर गर्व है, जिन्होंने अपनी त्वरित कार्रवाई और सतर्कता से किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को समय रहते रोकने में सहायता की।

जरांगे आंदोलन में पत्रकारों से बदसलूकी, प्रेस क्लब ने जताई नाराजगी; दक्षिण मुंबई का कारोबार ठप

(जीएनएस)।

मराठा आरक्षण आंदोलन की आड़ में पत्रकारों और आम कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन में महिला पत्रकारों और अन्य मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं।पत्रकारों ने आरोप लगाया कि आंदोलन स्थल पर उत्पीड़न और बदसलूकी की गई। (नवभारत रिपोर्ट के अनुसार)

इस घटना को लेकर मुंबई प्रेस क्लब ने कड़ी नाराजगी जताई है। प्रेस क्लब की ओर से जरांगे पाटिल को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रेस क्लब ने साफ कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र की

आवाज हैं और उनके साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, जरांगे और उनकी टीम से अनुशासन बनाए रखने, जवाबदेही तय करने और पत्रकारों की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।उधर, मराठा आंदोलन का असर अब दक्षिण मुंबई के कारोबार पर साफ नजर आने लगा है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विरेन शाह ने कहा कि आंदोलन के चलते दक्षिण मुंबई पूरी तरह ठप पड़ गई है। दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वीकेंड सेल तक बुरी तरह प्रभावित हुई है। शाह का कहना है कि आंदोलन के कारण ट्रैफिक जाम से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की कमाई आधी रह गई है, वहीं ग्राहक भी बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो दक्षिण मुंबई के व्यापार और रोजगार को दीर्घकालीन नुकसान झेलना पड़ेगा।

व्यापारियों ने राज्य सरकार से अपील की है कि तुरंत बातचीत कर समाधान निकाला जाए। उनका कहना है कि आंदोलन लंबा खिंचने से न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर असर होगा बल्कि रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है।

पूर्वोत्तर रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेने प्रभावित रहेगी

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-डोमिनगढ़ सेक्शन में तीसरी लाइन कमिशनिंग एवं गोरखपुर-नकहा जंगल स्टेशनों बीच दोहरीकरण के संबंध में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते अहमदाबाद मण्डल की कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

निरस्त ट्रेनें

- 25 सितंबर 2025 की 15045 गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस रद्द रहेगी
- 28 सितंबर2025 की 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी

आंशिक निरस्त ट्रेनें

- 23 सितंबर से 26 सितंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी तथा वाराणसी और गोरखपुर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 24 सितंबर से 27 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन से ऑरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी तथा गोरखपुर और वाराणसी स्टेशन के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 25 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19409 साबरमती-थावे एक्सप्रेस बस्ती स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी तथा बस्ती और थावे के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 27 सितंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19410 थावे-साबरमती एक्सप्रेस बस्ती स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी तथा थावे और बस्ती के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 21 सितंबर 2025 की 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा खलीलाबाद और गोरखपुर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेन

- 25 सितंबर, 2025 की ट्रेन संख्या 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया लखनऊ जं.-सुलतानपुर-वाराणसी-औड़िहार-छपरा-मुजफ्फरपुर स्टेशन के रास्ते चलेगी।

ट्रेनों के परिचालन, समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री

www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रेल संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने भावनगर मंडल के लोको पायलट को किया सम्मानित

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के लोको पायलट (भावनगर टर्मिनस) श्री संतोष कुमार को संरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा जुलाई-2025 के लिए "Man of the Month" अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान समारोह 01 सितम्बर, 2025 (सोमवार) को पश्चिम रेलवे मुख्यालय, चर्चगेट में आयोजित किया गया, जिसमें महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने श्री संतोष कुमार को मेडल एवं योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लोको पायलट श्री संतोष कुमार की तत्परता और सतर्कता से एक संभावित दुर्घटना को

टाला जा सका। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भी श्री संतोष कुमार को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने हेतु प्रोत्साहित किया।

मुंबई को मिलेगी हरियाली की नई सौगात, दहिसर-भांडुप और माहुल में बनेगा मैंग्रोव वन पार्क

(जीएनएस)।

मुंबई महानगर और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से घटते मैंग्रोव वनों को बचाने और पर्यटन को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। (नवभारत रिपोर्ट के अनुसार) गोराई में देश का पहला मैंग्रोव वन पार्क लगभग तैयार हो चुका है और अब सरकार ने दहिसर, भांडुप और माहुल में भी ऐसे ही मैंग्रोव वन पार्क बनाने का निर्णय लिया है।इन पार्कों को खासतौर पर इस तरह विकसित किया जाएगा कि लोग मैंग्रोव वनों की अनूठी जैव विविधता और तटीय पारिस्थितिकी को नजदीक से देख और समझ सकें। इसके लिए मैंग्रोव सफारी, बर्ड वॉचिंग टावर, ग्लास ब्रिज और अन्य पर्यटक आकर्षण शामिल किए जाएंगे। यहां आने वाले लोग पक्षियों की अलग-अलग प्रजातियों को करीब से देख सकेंगे और साथ ही प्राकृतिक तंत्र के महत्व को भी समझ पाएंगे। गोराई मैंग्रोव वन पार्क का निर्माण लगभग

19.76 एकड़ क्षेत्र में किया गया है और इसकी लागत करीब 33.43 करोड़ रुपये आई है। पार्क में एक प्रकृति व्याख्यान केंद्र, मैंग्रोव ट्रेल, पक्षी प्रयोगशाला और 800 मीटर लंबा पैदल मार्ग बनाया गया है। यह मार्ग सीधे मैंग्रोव क्षेत्र के बीच से होकर गुजरता है ताकि पर्यटक प्रकृति का असली अनुभव ले सकें। पार्क का काम अंतिम चरण में है और इसके जल्द खुलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार के मुताबिक, मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते प्रदूषण, औद्योगीकरण और अतिक्रमण से मैंग्रोव वनों का क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। इसी खतरे को देखते हुए साल 2013 में सरकारी भूमि पर स्थित मैंग्रोव क्षेत्रों को आरक्षित वन का दर्जा दिया गया और 2014 में इन पर विशेष नियंत्रण रखने के लिए अलग इकाइयां बनाई गईं। अब इस पहल को और मजबूत करने के लिए दहिसर, भांडुप और माहुल में नए पार्क बनाए जाएंगे। मैंग्रोव वन विभाग ने बताया कि तटीय इलाकों में वृक्षारोपण के लिए नर्सरियां भी तैयार की गई हैं और अवैध अतिक्रमणों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर होगा बल्कि मुंबईवासियों के लिए पर्यटन और मनोरंजन का नया ठिकाना भी बनेगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा 10 ट्रेनों का अहमदाबाद मण्डल के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 ट्रेनों का अहमदाबाद मण्डल के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है: (यात्रा प्रारंभ होने की तिथि से)

1. ट्रेन संख्या 20936/20935 इंदौर-गांधीधाम एक्सप्रेस का सामाख्याली स्टेशन पर ठहराव

ट्रेन संख्या 20936 इंदौर-गांधीधाम एक्सप्रेस 7 सितंबर 2025 से सामाख्याली स्टेशन पर 12.40 बजे आगमन तथा 12.42 प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 20935 गांधीधाम-इंदौर एक्सप्रेस 8 सितंबर 2025 से सामाख्याली स्टेशन पर 19.10 बजे आगमन तथा 19.12 प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन संख्या 16534/16533 बैंगलुरु-भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस का महेसाणा स्टेशन पर ठहराव

ट्रेन संख्या 16534 बैंगलुरु-भगत की कोठी एक्सप्रेस 7 सितंबर 2025 से महेसाणा स्टेशन पर 06.50 बजे आगमन तथा 06.52 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 16533 भगत की कोठी-बैंगलुरु एक्सप्रेस 10 सितंबर 2025 से महेसाणा स्टेशन पर 12.22 बजे आगमन तथा 12.24 बजे प्रस्थान करेगी।

3. ट्रेन संख्या 16312/16311 तिरुवनंतपुरम-श्रीगंगानगर साप्ताहिक एक्सप्रेस का महेसाणा स्टेशन पर ठहराव

ट्रेन संख्या 16312 तिरुवनंतपुरम-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस 6 सितंबर 2025 से महेसाणा स्टेशन पर 08.38 बजे आगमन तथा 08.40 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 16311 श्रीगंगानगर-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस 9 सितंबर 2025 से महेसाणा स्टेशन पर 05.45 बजे आगमन तथा 05.47 बजे प्रस्थान करेगी।

4. ट्रेन संख्या 12216/12215 बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस का महेसाणा स्टेशन पर ठहराव

ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस 3 सितंबर 2025 से महेसाणा स्टेशन पर 20.42 बजे आगमन तथा 20.44 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 12215 दिल्ली सराई रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस 4 सितंबर 2025 से महेसाणा स्टेशन 22.05 बजे आगमन तथा 22.07 बजे प्रस्थान करेगी।

5. ट्रेन संख्या 14311 बरेली-भुज एक्सप्रेस का मालिया-मियाणा स्टेशन पर ठहराव

ट्रेन संख्या 14311 बरेली-भुज आला हजरत एक्सप्रेस 04 सितंबर 2025 से मालिया-मियाणा स्टेशन पर 06.43 बजे आगमन तथा 06.45 बजे प्रस्थान करेगी।

6. ट्रेन संख्या 22915 बांद्रा टर्मिनस-हिसार एक्सप्रेस का सिद्धपुर स्टेशन पर ठहराव

ट्रेन संख्या 22915 बांद्रा टर्मिनस-हिसार एक्सप्रेस 8 सितंबर 2025 से सिद्धपुर स्टेशन पर 21.23 बजे आगमन तथा 21.25 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

गुजरात के फार्मास्युटिकल उत्पादन में उत्तर गुजरात का 12 फीसदी योगदान

फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है उत्तर गुजरात, वैश्विक स्तर पर उपस्थिति को मजबूत करने का है लक्ष्य

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित होगी फार्मास्युटिकल क्षेत्र में गुजरात की प्रगति

गांधीनगर, 01 सितंबर : गुजरात भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान के साथ 'फार्मा हब' बन गया है। गुजरात में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में हुई प्रगति का श्रेय सरकार की विभिन्न पहलों और निवेश के अवसरों को जाता है। बता दें कि गुजरात सन फार्मा, जायडस कैडिला, इंटास फार्मास्युटिकल्स और एमनील फार्मास्युटिकल जैसी ग्लोबल कंपनियों का ह्यघरह्ल है।

गुजरात के फार्मास्युटिकल उत्पादन में उत्तर गुजरात का 12 फीसदी योगदान

गुजरात के कुल फार्मास्युटिकल उत्पादन में उत्तर गुजरात का योगदान 12 फीसदी है। मेहसाणा में बल्क ड्रग का उत्पादन, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई), मध्यवर्ती और फॉमूर्लेशन में विशाल संभावनाएं हैं। टोरेंट फार्मा जैसी जानी-मानी कंपनियां के कारण इन अवसरों में वृद्धि हुई है। कंपनी का अमेरिकी दवा नियामक यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिट्रेशन (यूएस-एफडीए) द्वारा मान्यता प्राप्त प्लांट मेहसाणा जिले की कड़ी तहसील के इंद्राड़ गांव में स्थित है, जो वार्षिक 30 मिलियन वायल (शीशी) की क्षमता के साथ एपीआई और फॉमूर्लेशन, दोनों का उत्पादन करता है। इस प्लांट में ग्लोबल इंसुलिन उत्पादक नोवो नॉर्डिस्क के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। टोरेंट भारत में एकमात्र कंपनी है, जो नोवो नॉर्डिस्क के लिए समझौते के तहत इंसुलिन का उत्पादन करती है।

पाटण में छोटी और मध्यम फार्मा कंपनियों की मजबूत उपस्थिति है, जो इंजेक्टेबल और फॉमूर्लेशन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जिले में मेडटेक क्षेत्र में भी आशाजनक वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका नेतृत्व वैस्कुलर इंटरवेंशनल डिवाइस, हॉस्पिटल ट्रॉली और स्ट्रेचर जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियां कर रही हैं।

उत्तर गुजरात के मेहसाणा, पाटण और साबरकांठा जिलों में जीएमईआरएस (गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी) मेडिकल कॉलेजें स्थित हैं। इसके अलावा, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी (पाटण), गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (सिद्धपुर), एस.के. पटेल कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, गणपत यूनिवर्सिटी (खेरवा, मेहसाणा), बनास मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (पालनपुर), सिद्धपुर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तथा आर्डेक्टा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (खेड़ब्रह्मा) जैसी संस्थाएं स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकारी और निजी क्षेत्र के हॉस्पिटलों में व्यापक और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं, जो उत्तर गुजरात के हेल्थकेयर क्षेत्र को सुदृढ़ बनाती हैं। इस क्षेत्र में हेल्थकेयर का मजबूत नेटवर्क भी है, जिसमें 318 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 75 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शामिल हैं।

मजबूत इकोसिस्टम और रणनीतिक स्थान के साथ, आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस कार्यक्रम को सरकार, उद्योग और यूनिवर्सिटियों के बीच के मजबूत सहयोग का भी लाभ मिलेगा, जो देश के फार्मास्युटिकल उद्योग के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार हैं।

तीन लाख की चोरी से क्षेत्र में दहशत,चोरों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम और फरार हो गए

पुलिस की निष्क्रियता से अब तक अज्ञात चोरों ने लगभग दर्जन भर से अधिक लोगों के घरों दुकानों को निशाना बना चुके हैं।

(जीएनएस)।

माल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के माल क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कस्बे में हीरो शो रूम में बीती रविवार रात को लगभग साढ़े तीन लाख नकदी चुरा ले गये। साथ ही डीवीआर भी चुरा ले गये।

पीड़ित असलम ने बताया कि हमारा हीरो मोटरसाइकिल का असलम आटोकेयर नाम से शोरूम कस्बे के दक्षिणी छोर पर स्थित है। बीती रविवार रात को अज्ञात चोरों ने पीछे की खिड़की तोड़कर शोरूम में रखे 3,50,500 रुपये व डीवीआर उठा ले गये। सुबह जब शोरूम खोला तब जानकारी हुई।

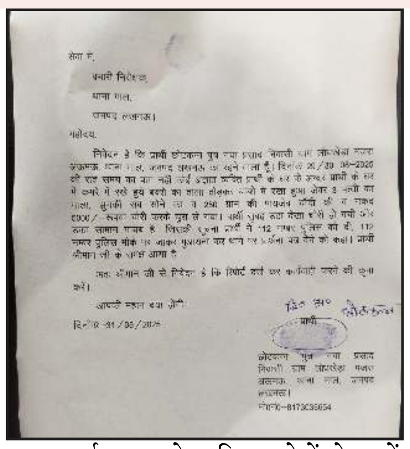

वहीं पुलिस की निष्क्रियता से अब तक अज्ञात चोरों ने लगभग दर्जन भर से अधिक लोगों के घरों दुकानों को निशाना बना चुके हैं, लेकिन पुलिस एक भी चोरी का पर्दाफाश नहीं कर पाई है। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि मोटरसाइकिल चोरी तो लगभग हर दूसरे दिन ही हो जाती है। इससे पूर्व गौरैया में तीन दुकानों, बरगदिया में तीन दुकानों, बीरपुर में और माल में अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की चोरी की जा चुकी है लेकिन पुलिस खाली हाथ है। इनमें आधे से अधिक मामलों को दर्ज तक नहीं किया गया है।

विकास खंड महमूदाबाद में तैनात ग्राम विकास अधिकारी श्रीकांत वर्मा के बड़े बोल कमरे में कैद कहा कि खा सकता हूं विधायक की विधायकी

बोले ग्राम विकास अधिकारी की मेरे पास बहुत से एविडेंस है जिससे विधायकी भी खा सकता हूं वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल

महमूदाबाद सीतापुर

सीतापुर बता दें कि विकासखंड महमूदाबाद में तैनात ग्राम विकास अधिकारी श्रीकांत वर्मा के बड़े बोल सीसीटीवी कैमरे हुए कैद और 54 सेकंड का यह वीडियो सुर्खियों में बन गया है और यह वीडियो में दिखने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं है यह ग्राम विकास अधिकारी के पद पर विकासखंड महमूदाबाद में तैनात है जिसने अपने ही मुखारविंद से बताया कि महोली के विधायक से मेरी बात बिगड़ चुकी है तथा जब मैं रेउसा ब्लॉक में तैनात था तो माननीय विधायक ज्ञान तिवारी ने मेरा ट्रांसफर करवा दिया था और कुछ नहीं कर पाए और मैं इतने एविडेंस रखता हूं कि विधायक की विधायकी भी खा सकता हूं आखिरकार यह शख्स विधायक की विधायकी खाने की बात क्यों कर रहा है जिसको लेकर सोशल मिडिया पर चचाओं का बाजार गर्म नजर आ रहा है अब यह ग्राम विकास

अधिकारी महमूदाबाद ब्लॉक में तैनात है तो क्या माननीय विधायका की विधायकी खा सकता है देखें सीसीटीवी कैमरे में कैद ग्राम विकास अधिकारी श्रीकांत वर्मा ने अपने ही मुखारविंद से किस तरह की टिप्पणी की माननीयों को लेकर जिससे जनता में गलत संदेश जा रहा है क्षेत्र में चर्चा इस बात की बनी हुई है कि आखिरकार ऐसी कौन से एविडेंस संबंधित विधायक के ग्राम विकास अधिकारी श्रीकांत वर्मा के पास है जिस विधायक की विधायकी भी जा सकती है अब देखना यह है कि क्षेत्रीय विधायिका की विधायकी खा जाता है या फिर ग्राम विकास अधिकारी पर उच्च अधिकारियों के द्वारा संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने एमनेस्टी योजना 2025 को स्वीकृति दी

(जीएनएस)।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपनी 196वीं ईएसआई बैठक में, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, एमनेस्टी योजना 2025 को मंजूरी दी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अनुमोदित एमनेस्टी योजना 2025 एक बार की विवाद समाधान पहल है जिसका उद्देश्य अदालती मामलों के बैकलॉग को कम करना और ईएसआई अधिनियम के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना है। 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी,(यह योजना नियोक्ताओं को ईएसआईसी के साथ अदालतों के बाहर कानूनी विवादों को निपटाने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती है।

31 मार्च 2025 तक, विभिन्न अदालतों में लगभग 27,000 मामले लंबित थे। इस योजना के तहतः

वास्तविक अंशदान और ब्याज का भुगतान करके तदर्थ मूल्यांकन का निपटान - कोई क्षतिपूर्ति नहीं ली जाएगी।

ऐसे मामलों को वापस लिया जाएगा जहां नियोक्ताओं ने पहले ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, बशर्ते कि विवादित क्षतिपूर्ति का 10% भुगतान किया जाए।

ईएसआईसी द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने या भुगतान में देरी के संबंध में दायर मामले, जिनका बाद में अनुपालन किया गया था, भी अदालत की अनुमति से वापस ले लिए जाएंगे।

31.03.2025 तक दायर किए गए अदालती मामले इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय निदेशकों और उप-क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अवधि के दौरान निकासी को संसाधित करने का अधिकार दिया गया है।

इस योजना से पहले सीमित अपील प्रावधानों और निकासी शक्तियों की कमी के कारण अनुपालन के बाद भी मुकदमेबाजी अक्सर लंबी खिंच जाती थी। एमनेस्टी 2025 इन कमियों को दूर करती है, विवाद समाधान के लिए एक व्यावहारिक और नियोक्ता-हितैषी मार्ग प्रदान करती है

भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक ने श्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में रेलवे कर्मचारियों को उन्नत बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

भारत के दो अग्रणी संस्थानों, दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक, भारतीय रेलवे (आईआर) और देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच आज एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह में माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार और एसबीआई के अध्यक्ष श्री सी.एस. शेट्टी की गरिमामयी मौजूदगी रही।

इस समझौता ज्ञापन के तहत, एसबीआई में वेतन खाते रखने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज में खासी वृद्धि की गई है। आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में, बीमा लाभ को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि सीजीईजीआईएस के तहत आने वाले समूह ए,बी और सी के कर्मचारियों के लिए वर्तमान कवरेज क्रमशः 1.20 लाख रुपए, 60,000 रुपए और 30,000 रुपए है।

इसके अलावा, एसबीआई में केवल वेतन खाता रखने वाले सभी रेलवे कर्मचारी, अब बिना किसी प्रीमियम का भुगतान किए या किसी मेडिकल जांच के 10 लाख रुपए के प्राकृतिक मृत्यु बीमा कवरेज के पात्र होंगे।

करीब 7 लाख रेलवे कर्मचारियों के एसबीआई में वेतन खाते होने के कारण, यह समझौता कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो भारतीय रेलवे और एसबीआई के बीच एक संवेदनशील और मानवीय साझेदारी को दर्शाता है।

इस समझौता ज्ञापन के तहत कुछ प्रमुख पूरक बीमा कवर में शामिल हैं: 1.60 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर और रुपे डेबिट कार्ड पर 1.00 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त कवर, 1.00 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना (स्थायी पूर्ण विकलांगता) कवर और 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना (स्थायी आंशिक विकलांगता) कवर।

दो प्रमुख संस्थाओं के बीच यह समझौता ज्ञापन कर्मचारी-केंद्रित, मानवीय भावनाओं के अनुकूल है और खासकर ग्रुप सी और अन्य अग्रिम पंक्ति के रेलवे कर्मियों को विशेष लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

सरकार ने वस्त्र उद्योग की शानदार प्रतिक्रिया के बाद उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है

आवेदन 30 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है

(जीएनएस)।

उद्योग हितधारकों से प्राप्त मजबूत और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अगस्त 2025 में आवेदन के हालिया आमंत्रण के दौरान एमएमएफ परिधान, एमएमएफ वस्त्र और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र से 22 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सरकार संभावित निवेशकों को योजना से लाभ प्राप्त करने का एक और अवसर प्रदान कर रही है।

वस्त्र उद्योग की इस योजना के अंतर्गत और अधिक निवेश करने की इच्छा के आधार पर वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना हेतु आवेदन विंडो पुनः खोली जा रही है। यह पीएलआई वस्त्र योजना के अंतर्गत देश में वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण के कारण बढ़ते बाजार और उत्पन्न विश्वास का परिणाम है।

आवेदन विंडो 24.09.2021 को अधिसूचित पीएलआई वस्त्र योजना और 28.12.2021 को जारी पीएलआई वस्त्र योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर खोली जा रही है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है।

योजना के लिए आवेदन विंडो 30 सितंबर, 2025 तक उसी ऑनलाइन पोर्टल पर खुली रहेगी, आवेदन विंडो बंद होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अब तक पीएलआई योजना के तहत 28,711 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 74 भागीदार कंपनियों को लाभार्थियों के रूप में चुना गया है। ये निवेश एमएमएफ मूल्य श्रृंखला में सम्पूर्ण वस्त्र उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू का दौरा किया और जम्मू संभाग के वर्षा, बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू का दौरा किया और जम्मू संभाग के वर्षा, बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। गृह मंत्री जम्मू में चक मांगू गांव के बाढ़-प्रभावित लोगों से भी मिले।

श्री अमित शाह ने तवी पुल, शिव मंदिर और जम्मू में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए घरों का भी निरीक्षण किया।

दौरे के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में ताजा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला, केन्द्र सरकार एवं केन्द्रशासित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल की घटनाओं में हुई जन-हानि पर दुख व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि संकट की इस घड़ी में, पहले दिन से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केन्द्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है और भारत सरकार ने बचाव कार्यों में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। श्री शाह ने कहा कि केन्द्रशासित प्रदेश और सभी एजेंसियों ने मिलकर संभावित नुकसान को बहुत कम किया है और समन्वित प्रयासों के साथ हम कई जानें बचाने में सफल हुए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सभी अर्ली वॉर्निंग एप्स (एहअर) की पद्धतियों, उनकी सटीकता और उनकी जमीनी पहुँच का क्रिटिकल एनिलिसिस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार-बार समीक्षा कर व्यवस्था में सुधार करना ही हमें जीरो कैजुअल्टी अप्रोच की दिशा में लेकर जा सकता है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मौसम विभाग व ठउ्टअ को डेटा एनालिटिक्स और अक के उपयोग से बादल फटने के कारणों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (ऋछक) पर्याप्त राशन की व्यवस्था करे और 10 दिन बाद कनेक्टिविटी की स्थिति को देखते हुए राशन की डिलिवरी ऑफलाइन करने का निर्णय लिया जा सकता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि एक-दो दिन में ही गृह मंत्रालय की सर्वेक्षण टीमें यहाँ नुकसान का जायजा लेने आएंगी और उसके बाद सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और जल विभाग को सक्रिय होकर जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और वायु सेना के मेडिकल दस्तों की सहायता ली जा सकती है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि चूँकि जम्मू-कश्मीर प्राकृतिक आपदा-संभावित क्षेत्र है इसीलिए केन्द्र के हिस्से के रूप में राज्य आपदा मोचन निधि (रउ्रऋ) के लिए 209 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रशासित प्रदेश को आवंटित की गई है, जिससे यहाँ राहत कार्य शुरू हो गया है।

गृह मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार और केन्द्रशासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (वळउ्टअ) द्वारा समय पर दी गई चेतावनियों से जन-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (ठउ्रऋ), सेना, केन्द्रशासित प्रदेश आपदा मोचन बल (वळउ्रऋ), अन्य प्रतिक्रिया दल, सभी अलर्ट पर थे और हेलीकॉप्टर भी तैयार थे। उन्होंने कहा कि सेना और ठउ्रऋ की तैनाती के बारे में भी सभी को सूचित कर दिया गया था।

श्री अमित शाह ने कहा कि लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचा है और क्षतिग्रस्त घरों के लिए रउ्रऋ के तहत सहायता का आकलन किया जा रहा है और इसे जल्द से जल्द वितरित किया जाएगा।

भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का बढ़ता परिवार

भाकियू लोकतांत्रिक संगठन के

जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में अनुभव सिंह यादव को युवा मोर्चा जिला सचिव पद पर नियुक्त किया गया अतुल कुमार, जिला अध्यक्ष लखनऊ ने उन्हें सदस्यता पत्र प्रदान किया। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान की देखरेख में हुई है।

- नवनियुक्त पदाधिकारीः अनुभव सिंह यादव, युवा मोर्चा जिला सचिव
- नियुक्ति करने वालेः अतुल कुमार, जिला अध्यक्ष लखनऊ
- संगठन के प्रमुखः राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष
- अन्य पदाधिकारीः राकेश अवस्थी (दद्दू), युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष
- मीडिया प्रभारीः निखिल मिश्रा, मलिहाबाद तहसील
- ग्राम अध्यक्षः अंकित रावत, नेजाभरी ग्राम

इस नियुक्ति से संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने में मदद मिलेगी। भाकियू लोकतांत्रिक संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अनुभव सिंह यादव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी

बेस रिपेयर डिपो, बानी कैंप में कमान परिवर्तन

(जीएनएस)।

एयर कमोडोर वेंकटेश्वरन कृष्ण कुमार ने 01 सितंबर 2025 को एयर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में वायु सेना स्टेशन बानी कैंप, नजफगढ़ की कमान संभाली है। उन्होंने एयर कमोडोर अमित अग्रवाल से कार्यभार ग्रहण किया।

भारतीय वायु सेना की एई (एल) शाखा में 22 नवंबर 1998 को कमीशन प्राप्त करने वाले एयर कमोडोर कृष्ण कुमार का करियर बहुत ही उत्‍ कृ‍ ट रहा है। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर ऑफ साइंस और रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डीआईएटी), पुणे से एम.टेक की डिग्री प्राप्त की है।

अपनी विशिष्ट सेवा के दौरान, उन्होंने भारतीय वायु सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनके शानदार कैरियर में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (वायु सेना) के हिस्से के रूप में ताजिकिस्तान में प्रतिनियुक्ति और इटली में एक सर्विस कोर्स शामिल है। अनुकरणीय समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और वायु सेना प्रमुख दोनों से सराहना प्रा‍ त हुई है।

एक सच्चे खिलाड़ी और पेशे से इंजीनियर, एयर कमोडोर कृष्ण कुमार में विशाल अनुभव और गतिशील नेतृत्व क्षमता दोनों का समावेश है। इस अवसर पर, उनकी पत्नी श्रीमती पुष्कला ने श्रीमती सीमा अग्रवाल का स्थान लेते हुए वायु सेना परिवार कल्याण संघ (स्थानीय) की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया

सीतापुर के पहले में मनाया जाएगा परियार ललई सिंह यादव का जन्मदिन

पहला सीतापुर

सीतापुर पहला में मनाया जाएगा परियार ललई सिंह यादव का जन्मोत्सव सीतापुर पहला विकासखंड की ग्राम पंचायत बहटूरपुर के मजरा पिपरा बाजार स्थित अंबेडकर पार्क में 01 सितंबर 2025 को पेरियार ललई सिंह यादव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा यह आयोजन भारतीय बुद्ध डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति पिपरा द्वारा किया जा रहा है इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मा.आर.के.चौधरी (सांसद मोहनलालगंज) शामिल होंगे विशिष्ट अतिथियों में पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भर्गोव ब्लॉक प्रमुख अजय

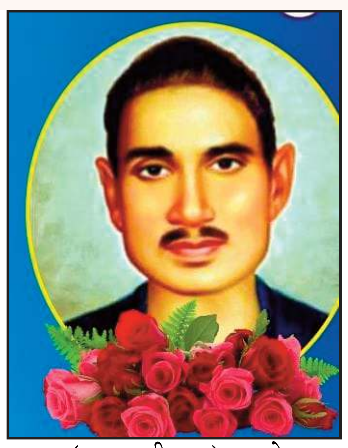

यादव (पहला सीतापुर) सहयोग छात्र शिक्षा समिति के प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार भीम आर्मी से अमरीश बौद्ध (विधानसभा सिधौली) यो भीम आर्मी संयोजक निर्मल पासि उपस्थित रहेंगे और समाज सुधार पर अपना संबोधन देंगे कार्यक्रम में,शैलेंद्र राजवंशी, सुनिल राठौर, डॉक्टर सरोज, रमेश चंद्र प्रधान, गोविंद, ललित चौधरी, अजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार भास्कर, अमरेश कुमार बौद्ध, एम.के. सिंघानिया, गौरव सिंह, सुरेश, प्रकाश, रंजीत चौधरी, सूरज लाल, श्यामू , शुभम, जयकरन, अशोक, जागेश्वर नेता समेत क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग शिरकत करेंगे आयोजकों को क्षेत्र वासियों से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है

बुलडोजर की कार्रवाईः सत्ता पक्ष के इशारे पर अतिक्रमण हटाने का दावा, न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप

महमूदाबाद सीतापुर

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम मियांपुरवा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के इशारे पर बुलडोजर से कई मकानों और दुकानों को गिरा दिया गया। इस कार्रवाई में छोटेलाल विश्वकर्मा पुत्र राम प्यारे विश्वकर्मा, यासीन पुत्र अब्दुल रहमान, रामजीवन गुप्ता, मौलाना मुनीर तथा मो. इस्लाम के मकानों और दुकानों को निशाना बनाया गया। आरोप है कि यह कार्रवाई मा. उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के आदेशों की अवहेलना करते हुए की गई, जिसमें इन मकानों और दुकानों की पक्की पैमाइश किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इतना ही

नहीं, यह मामला तहसील महमूदाबाद में भी लंबित है। स्थानीय निवासियों और पीड़ित परिवारों का आरोप है कि सत्ता पक्ष के दबाव में यह कार्रवाई की गई है, जबकि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। इस घटना ने क्षेत्र में आक्रोश और असंतोष को बढ़ा दिया है। पीड़ित परिवारों ने न्यायालय के आदेश का पालन न करने और सत्ता पक्ष के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है।